बाल किशन गिरी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 2010 की 555)

28 मई 2014

[डॉ। बी.एस.चौहान और ए.के.सीकरी, जे.जे]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971-एस। 12-एक वकील द्वारा आपराधिक अवमानना- के तहत दोषसिद्धि- आवेदन और शिकायत वकील द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाना- वकील द्वारा माफी मांगी गई- अधिनियम के तहत दोषसिद्धि- का औचित्य- माना गया: उच्च न्यायालय ने वकील की माफी स्वीकार नही करने में कोई त्रुटि नहीं की क्योंकि यह सदभावी नहीं है- द्वारा लगाए गए आरोप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ वकील बहुत गंभीर, निंदनीय और कानून की महिमा और अदालत की गरिमा को कमजोर करने के लिए पर्याप्त हैं और बिना किसी आधार के हैं- बार का सदस्य होने के नाते, यह उनका कर्तव्य था कि वह न्याय की महिमा का निरादर और अपमान न करें। कानून की अदालत द्वारा दिए गए न्याय के बारे में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ परोक्ष, अप्रमाणित- आक्षेप लगाने से न केवल संबंधित न्यायाधीशों को पीड़ा और कष्ट होता है, बल्कि न्याय प्रदान

करने के अपने कार्य में न्यायपालिका में जनता का विश्वास भी हिल जाता है। न्याय-न्यायिक प्रक्रिया ईमानदारी पर आधारित है। निष्पक्षता और तटस्थता जो निर्विवाद है- ऐसा कृत्य अत्यधिक निंदनीय है और गहरा खेद है- हालाँकि, रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वकील पर 20,000/- को घटाकर 2,000/- कर दिया गया।

न्यायालय की अवमानना- मांगी गई माफी- का अर्थ- माना गया: माफी का मतलब असफलता के लिए खेदजनक स्वीकारोक्ति या बहाना है- माफी ईमानदारी से होनी चाहिए- माफी वास्तविक ग्लानि और पश्चाताप की भावना के साथ पेश की जानी चाहिए, न कि सजा से बचने के लिए सोची-समझी रणनीति के साथ- आपराधिक अवमानना के मामले में जल्द से जल्द माफी मांगी जानी चाहिए क्योंकि देर से माफी मुश्किल से ग्लानि दर्शाती है।

न्यायालय की अवमानना- दंड देने की अदालतों की शक्ति- अभिनिर्धारित: अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायिक शक्ति की एक दुर्लभ प्रकार है- इसमें बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ प्रयोग की आवश्यकता होती है- शक्ति का प्रयोग केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां चुप्पी अब कोई विकल्प नहीं है- शक्ति अदालतों द्वारा अवमानना के लिए दंडित करने का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में सार्वजनिक सम्मान और विश्वास को सुरक्षित करना है।

अपीलकर्ता का भतीजा दो अन्य लोगों के साथ मृत पाया गया था। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की. कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता-वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन और शिकायत दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी आपराधिक गतिविधियों में शामिल गैंगस्टर थे और स्थानीय विधायक और पूर्व विधायक से निकटता से जुड़े हुए थे तथा एमपी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ भी संबंध थे। यह आरोप लगाया गया था कि न्यायाधीश आरोपी व्यक्तियों को जमानत दिलाने का पक्ष लेंगे। उच्च न्यायालय ने मामले की जांच की और कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही की जाए। अपीलकर्ता ने बिना शर्त माफी मांगी कि उसे वकील ने गुमराह किया था और वह अपने भतीजे की हत्या के कारण तनाव में था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को अदालत की अवमानना धिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत आपराधिक अवमानना करने के लिए दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई। इसलिए, तत्काल अपील।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित:

1.1. अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के

खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर, निंदनीय और, माना जाता है, कानून की महिमा और अदालत की गरिमा को कमजोर करने के लिए पर्याप्त हैं और वह भी बिना किसी आधार के। अपीलकर्ता एक प्रैक्टिसिंग वकील है। उनके द्वारा यह दलील दी गई कि उन्हें अन्य अधिवक्ताओं द्वारा गुमराह किया गया था, यह बाद में लिया गया विचार है। उन्होंने जो लिखा है उसके परिणामों के बारे में उन्हें पूरी तरह से पता होना चाहिए। इस आशय का कथन कि अध्याय के प्रावधान XXXV-E के नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जाना महत्वहीन बना हुआ है क्योंकि अपीलकर्ता ने न केवल शिकायत बल्कि उसकी सामग्री को भी लिखना स्वीकार किया है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की माफी स्वीकार न करके कोई त्रुटि नहीं की क्योंकि वह सदभावी नहीं थी। हो सकता है कि अपीलकर्ता का आंतरिक आक्रोश रहा हो क्योंकि अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके भतीजे की हत्या कर दी गई थी, लेकिन एक प्रैक्टिसिंग वकील के लिए अदालत के खिलाफ उंगली उठाने का यह कोई बहाना नहीं था। [पैरा 8,19] [555-बी-सी; 559-डी-ई]

एम.बी. सांघी, एडवोकेट बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य। 1991 (3) एससीआर 312: एआईआर 1991 एससी 1834; आशाराम एम. जैन बनाम ए.टी. गुप्ता एवं अन्य। 1983 (3) एससीआर 719: एआईआर 1983 एससी 1151 संदर्भित।जेनिसन बनाम बेकर [1972] 1 सभी ई.आर. 997 संदर्भित।

1.2. माफ़ी का अर्थ विफलता के लिए खेदजनक स्वीकारोक्ति बहाना है। किसी के कृत्य से प्रभावित व्यक्ति को यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि उसका कोई अपराध करने का इरादा नहीं था, साथ ही जो कुछ किया गया हो उसके लिए खेद की अभिव्यक्ति भी। माफी ईमानदारी से निर्विवाद होनी चाहिए। इसे वास्तविक ग्लानि और पश्चाताप की भावना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि सजा से बचने के लिए एक सोची-समझी रणनीति के साथ। ऐसी माफ़ी को केवल "कागज़ी माफ़ी" कहा जा सकता है। [पैरा 12 और 13] [556-ई-एफ; 557-सी]

1.3. न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 12 का खंड 1 और स्पष्टीकरण अदालत को अदालत की संतुष्टि के लिए माफी मांगने पर अदालत की अवमानना करने के लिए दी गई सजा को माफ करने में सक्षम बनाता है। हालांकि माफी को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि यह इसी काबिल है या देरी से मांगी गइ है, भले ही आरोपी ने इसे सदभाविक रूप से कहा है। ऐसा आचरण जो अदालत की न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है और उसका मजाक उड़ाता है, उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और कोई व्यक्ति न्याय प्रशासन को रोकने, पक्षपात करने, उसमें बाधा डालने या उसमें हस्तक्षेप करने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां माफ़ी मांगने की समझदारी बाद के चरण में ही सामने आती है। निःसंदेह, माफ़ी किसी कृत्य के लिए बचाव, औचित्य या उचित सज़ा नहीं हो सकती है जो

अदालत की अवमानना के समान है। माफी उस स्थिति में स्वीकार की जा सकती है जहां जिस आचरण के लिए माफी दी गई है वह ऐसा है कि इसे "अदालत की गरिमा से समझौता किए बिना नजरअंदाज किया जा सकता है", या इसका उद्देश्य वास्तविक पश्चाताप का सबूत होना है। अदालत की आपराधिक अवमानना के लिए माफी जल्द से जल्द पेश की जानी चाहिए क्योकि देर से मांगी गई माफी कदाचित ही उस"पश्चाताप को दर्शाती है जो अवमानना के शुद्धिकरण का सार है" । [पैरा 13 और 15] [557-ए-सी, एफ; 556-जी-एच]

देब्ब्रत बंदोपाध्याय और अन्य। पशिचम बंगाल राज्य और अन्य। 1969 एससीआर 304: एआइआर 1969 एससी 189; मुलख राज बनाम पंजाब राज्य एआइआर 1972 एससी 1197; सचिव,हैलाकांडी बार एसोसिएशन बनाम असम राज्य और अन्य। 1996 (2) पूरक। एससीआर 573: एआइआर 1996 एससी 1925; सी एलुमलाइ एवं अन्य।वी.ए.जी.एल. इरूदयाराज और अन्य। 2009 (4) एससीआर 774: एआइआर 2009 एससी 2214;रणवीर यादव बनाम बिहार राज्य 2010 (6) एससीआर 1073:(2010) 11 एससीसी 493; श्री बरदाकांत मिश्रा बनाम उडीसा उच्च न्यायालय के रजिस्टार एवं अन्य। 1974 (2) एससीआर 282 एआइआर 1974 एससी 710: बार काउंसिल आफ महाराष्ट बनाम एम.वी.दाभोलकर आदि 1976 (2) एससीआर 48: एआइआर 1976 एससी 242;आशाराम एम.जैन बनाम एटी गुप्ता एवं अन्य। 1983 (3) एससीआर 719:

एआइआर 1983 एससी1151; मो. जहीर खान बनाम विजय सिंह और अन्य। एआइआर 1992 एससी 642; पुनः संजीव दता 1995 (3) एससीआर 450: (1995) 3 एससीसी 619;पटेल रजनीकांत धुलाभाइ एवं अन्य। बनाम पटेल चंद्रकांत धुलाभाइ और अन्य 2008 (10) एससीआर 1169: एआइआर 2008 एससी 3016;विश्राम सिंह रघुबंशी बनाम यूपी राज्य 2011 (8) एससीआर 105: एआइआर 2011 एससी 2275 पर निर्भर था।

एलडी जैकवाल बनाम यूपी राज्य 1984 (3) एससीआर 833: एआईआर 1984 एससी 1374; टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम अशोक खोत और अन्य 2006 (2) सप्ल। एससीआर 215: एआईआर 2006 एससी 2007- संदर्भित।

1.4. अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायिक शक्ति का एक दुर्लभ प्रकार है जिसे अपने स्वभाव से ही बहुत सावधानी और सतर्कता से प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां "चुप्पी अब कोई विकल्प नहीं है।" अवमानना के लिए दंडित करने की अदालतों की शक्ति न्यायिक प्रक्रिया में सार्वजनिक सम्मान और विश्वास को सुरक्षित करना है। इस प्रकार, यह न्याय की प्रत्येक अदालत के लिए एक आवश्यक प्रकिया है। [पैरा 17] [558-एफ-एच; 559-ए]

पुन: एस. मुलगावकर 1978 (3) एससीआर 162: एआईआर 1978 एससी 727; एच.जी. रंगनगौड बनाम मेसर्स स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य। 2011 (13) एससीआर 97: एआईआर 2012 एससी 490; मनिंदरजीत सिंह बिट्टव. भारत संघ एवं अन्य, (2012) 1 एससीसी 273; टी.सी. गुप्ता एवं अन्य. वी. हरि ओम प्रकाश और अन्य। (2013) 10 एससीसी 658; अरुण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। जिला न्यायाधीश के माध्यम से, 2013 (6) एससीआर 263:(2013) 14 एससीसी 127- पर भरोसा किया गया।

1.5. बार का सदस्य होने के नाते, अपीलकर्ता का यह कर्तव्य था कि वह अदालत द्वारा दिए गए न्याय की महिमा का अनादर और अपमान न करे। यह एक ऐसा मामला है जहां एक प्रैक्टिसिंग वकील ने उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के खिलाफ पूर्वाग्रह और पूर्वनिर्धारित मानसिकता का आरोप लगाया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद, परोक्ष, निराधार आरोप लगाने से न केवल संबंधित न्यायाधीशों को पीड़ा और पीड़ा होती है, बल्कि न्याय प्रदान करने के कार्य में न्यायपालिका में जनता का विश्वास भी कम जाता है। न्यायिक प्रक्रिया ईमानदारी, तटस्थता और निष्पक्षता पर आधारित है जो निर्विवाद है। विशेष रूप से बार के सदस्यों द्वारा किया गया ऐसा कृत्य अत्यंत निंदनीय और अत्यंत खेदजनक है। प्रेरणा का अभाव कोई बहाना नहीं है. [पैरा 18] [559-ए-डी]

1.8 उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता पर लगाया गया 20,000/- रुपये का जुर्माना घटाकर 2,000/- रुपये कर दिया गया है। [पैरा21] [560-ए]

केस कानून संदर्भ:

1991 (3) एससीआर 31	उल्लेख किया गया है	पैरा 9
1983 (3) एससीआर 719	उल्लेख किया गया है	पैरा 10
[1972] 1 सभी ई.आर. 997	उल्लेख किया गया है	पैरा 11
1984 (3) एससीआर 833	उल्लेख किया गया है	पैरा 14
2006 (2) पूरक। एससीआर 215	उल्लेख किया गया है	पैरा 14
1969 एससीआर 304	पर भरोसा	पैरा 15
एआईआर 1972 एससी 1197	पर भरोसा	पैरा 15
1996 (2) सप्ल. एससीआर 573	पर भरोसा	पैरा 15
2009 (4) एससीआर 774	पर भरोसा	पैरा 15
2010 (6) एससीआर 1073	पर भरोसा	पैरा 15
1974 (2) एससीआर 282	पर भरोसा	पैरा 16
1976 (2) एससीआर 48	पर भरोसा	पैरा 16
1983 (3) एससीआर 719	पर भरोसा	पैरा 16

एआईआर 1992 एससी 642	पर भरोसा	पैरा 16
1995 (3) एससीआर 450	पर भरोसा	पैरा 16
2008 (10) एससीआर 1169	पर भरोसा	पैरा 16
2011 (8) एससीआर 105	पर भरोसा	पैरा 16
1978 (3) एससीआर 162	पर भरोसा	पैरा 17
2011 (13) एससीआर 97	पर भरोसा	पैरा 17
(2012) 1 एससीसी 273	पर भरोसा	पैरा 17
(2013) 10 एससीसी 658	पर भरोसा	पैरा 17
2013 (6) एससीआर 263	पर भरोसा	पैरा 17

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 555/2010

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अवमानना आवेदन संख्या(सीआरआई) 15 / 2009 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.02.2010 से।

अपीलकर्ता की ओर से जीतेन्द्र मोहन शर्मा, शिखा बानी, समीर सिंह, पहलाद सिंह शर्मा।

प्रतिवादी की ओर से इरशाद अहमद, एएजी, अभिष्ठ कुमार, अर्चना सिंह।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ। बी.एस. चौहान, जे. 1. इस अपील में, अवमानना आवेदन (सीआरएल) संख्या 15/2009 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 5.2.2010 का आक्षेपित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा 'अपीलकर्ता को प्रावधानों के तहत आपराधिक अवमानना करने के लिए दोषी ठहराया गया था। न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत एक महीने के लिए साधारण कारावास और 20,000/- रुपये का जुर्माना भरने और डिफ़ॉल्ट रूप से दो सप्ताह के लिए साधारण कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है। घोर निंदा की गयी।

2. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियाँ हैं

वह:

A. पी.एस. में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 23.5.2008 को बलेनी, जिला बागपत में अपीलकर्ता अनिल कुमार ने 2010 की आपराधिक अपील संख्या 686 में आरोप लगाया कि उसका छोटा भाई सुनील कुमार और पुनीत कुमार गिरि, जो मेरठ कॉलेज के सीताराम छात्रावास में रहते थे, का पता नहीं चल सका और पिछली शाम से गायब है। उसी छात्रावास के एक अन्य सहनिवासी सुधीर कुमार के भी लापता होने की सूचना है। अगले ही दिन उक्त लापता व्यक्तियों के तीन शव हिंडन नदी के किनारे मिले। इसलिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया।बी. जांच के दौरान,

पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में यह आया कि घटना स्थल पी.एस.कोतवाली, मेरठ, के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है और इस प्रकार जांच जारी है ।

पी.एस. में स्थानांतरित किया जा रहा है मामला कोतवाली, मेरठ में मुकदमा अपराध संख्या 190/2008 के रूप में दर्ज किया गया था।

सी. जांच के दौरान हाजी इज़लाल सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मेरठ जिले के समक्ष जमानत याचिका दायर की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। व्यथित होकर सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष जमानत याचिका दायर की। उक्त आवेदनों के लंबित रहने के दौरान 14.8.2009 को अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी गैंगस्टर थे और उन्होंने अपनी आपराधिक गतिविधियों से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। आरोपी व्यक्ति एक स्थानीय विधायक और पूर्व. एमपी के करीबी रिश्तेदार थे। और उनके श्री न्यायमूर्ति एस.के. जैन सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ संबंध थे। जैन जो पहले मेरठ कोर्ट में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। अपीलकर्ता ने यह आशंका व्यक्त की कि श्री न्यायमूर्ति एस.के. जैन आरोपी व्यक्तियों को जमानत दिलाने का पक्ष लेंगे। उक्त शिकायत की एक प्रति बार काउंसिल ऑफ यूपी के अध्यक्ष को

भी भेजी गई थी।

डी. उच्च न्यायालय ने शिकायत की जांच की और मामले को 12.11.2009 को न्यायिक पक्ष में रखा। अदालत ने अपीलकर्ता को दिनांक 14.8.2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उसके खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।

ई. अपीलकर्ता ने दिनांक 21.11.2009 को बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि आवेदन उसके द्वारा भेजा गया था क्योंकि जिला मेरठ के अधिवक्ताओं ने उसे गुमराह किया था और वह बहुत मानसिक तनाव में था क्योंकि उसके भतीजे की हत्या कर दी गई थी।

एफ. उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद दिनांक 5.2.2010 के फैसले और आदेश के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और यहां ऊपर बताए अनुसार सजा सुनाई।

इसलिए, यह अपील

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जे.एम. शर्मा ने प्रस्तुत किया है कि कारण बताओ नोटिस इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 (इसके बाद इसे नियम कहा जाएगा) के नियम 6 के अध्याय XXXV-E के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। नियम)। इस प्रकार, बाद की सभी कार्यवाही निष्प्रभावी हो गई। और तो और, अपीलकर्ता

एक प्रैक्टिसिंग वकील है और उसने उक्त शिकायत मानसिक तनाव में लिखी थी क्योंकि उसके भतीजे की हत्या कर दी गई थी, और मेरठ कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा गुमराह किए जाने पर उसने उक्त शिकायत लिखी थी। एक बार जब अपीलकर्ता ने पूर्ण और बिना शर्त माफी मांग ली, तो सजा की आवश्यकता नहीं थी और लगाया गया जुर्माना अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। अत: अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री इरशाद अहमद ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि अपीलकर्ता द्वारा न केवल एक न्यायाधीश के खिलाफ बल्कि विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ बहुत ही हिंसक और निंदनीय आरोप लगाए गए थे और केवल माफी मांगना उचित नहीं है। जैसा कि अपीलकर्ता ने स्वीकार किया था कि उसने पत्र लिखा था और उसकी विषयवस्तु भी उसी की थी और उसे जारी किये गये कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया, वैधानिक नियमों का पालन नहीं किये जाने मात्र से आदेश को रद् द नहीं किया जावेगा । अपील में योग्यता नहीं है और यह खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है

उभय पक्षों के विद्वान वकील ने अभिलेख का अवलोकन किया

6. अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "4. अखलाख परिवार के मेरठ में तैनात सभी न्यायाधीशों से अच्छे संबंध हैं। माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.सी. निगम वर्ष 1981 से 1984 और 2002-03 में अपर सिविल जज/ए.सी.जे.एम. और एडीसी जिले के पद पर मेरठ में तैनात थे। और सत्र न्यायाधीश क्रमशः। माननीय न्यायाधीश श्री एस.के. जैन 2002-03 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में मेरठ में भी तैनात थे।

5. माननीय. जस्टिस वी.के. वर्मा, माननीय. जस्टिस एस.के. जैन और माननीय. जस्टिस एस.सी. निगम को जिला न्यायाधीशों के कैडर से उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया है। माननीय. न्यायमूर्ति श्री एस.के. जैन एवं मा. न्यायमूर्ति एस.सी. निगम वर्ष 2002-03 में एक साथ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में सिविल कोर्ट मेरठ में तैनात रहे और उन्हें मेरठ जजशिप से जिला न्यायाधीश के कैडर में पदोन्नत किया गया। वे बहुत अच्छे दोस्त हैं. माननीय. श्री न्यायमूर्ति वी.के. वर्मा की भी उनसे काफी अच्छी घनिष्ठता है. उन्होंने वी.पी.श्रीवास्तव जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ट अधिवक्ता है के साथ अवैध रूप से और गुप्त उददेश्यों के साथ आपराधिक मामलों में ज्ञात आरोपियों को

बडी जमानत देने के लिए एक दल बनाया है। माननीय. न्यायमूर्ति वी.के. वर्मा ने मेरठ के उपरोक्त प्रसिद्ध तिहरे हत्याकांड में रिजवान और वसीम नाम के दो आरोपियों को 17.7.2009 को जमानत आवेदन संख्या 2009 की 924 और 2009 की 1238 में अवैध रूप से और गुप्त उद्देश्यों से जमानत दे दी है।"

7. अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने आगे यह आशंका व्यक्त की कि उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है क्योंकि वे श्री वी.पी. के आदेश पर कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता।

कुल मिलाकर, आरोप का आपत्तिजनक हिस्सा इस प्रकार था।

(1) जब अखलाक की पोस्टिंग तीन टर्म तक मेरठ में हुई तभी से उनके मिस्टर जस्टिस एस.सी. निगम से अच्छे संबंध थे। (2) कि न्यायमूर्ति वी.के. वर्मा की आरोपियों के परिवार से अच्छी घनिष्ठता थी और आरोपियों ने वी.पी. श्रीवास्तव के साथ मिलकर एक गुट बना लिया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पर अवैध रूप से और गुप्त उद्देश्यों से बड़ी जमानतें हासिल करने का आरोप है। न्यायमूर्ति श्री वीके वर्मा ने रिजवान और वसीम नाम के दो अभियुक्तों की अवैध रूप से और गलत मंशा से जमानत स्वीकार कर चुके हैं। तीन न्यायाधीश (वी.के. वर्मा,

एस.के. जैन और एस.सी. निगम) वी.पी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता के आदेश पर कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। ।

8. अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर, निंदनीय और स्वीकार्य हैं, जो कानून की महिमा और अदालत की गरिमा को कमजोर करने के लिए पर्याप्त हैं और वह भी बिना किसी आधार के। अपीलकर्ता एक प्रैक्टिसिंग वकील है। उनके द्वारा यह दलील दी गई कि उन्हें अन्य अधिवक्ताओं द्वारा गुमराह किया गया था, यह बाद में लिया गया विचार है। उन्होंने जो लिखा है उसके परिणामों के बारे में उन्हें पूरी तरह से पता होना चाहिए। इस आशय का दावा कि नियमों के अध्याय XXXV-ई के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था, महत्वहीन बना हुआ है क्योंकि अपीलकर्ता ने न केवल शिकायत को बल्कि उसकी सामग्री को भी लिखने की बात स्वीकार की है। अपीलकर्ता ने न्यायिक पक्ष में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया था। ऐसी तथ्य-स्थिति में, भले ही तर्क के लिए यह स्वीकार कर लिया जाए कि उपरोक्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया है, हम अपीलकर्ता के मामले को इस कारण से स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि श्री जे.एम. शर्मा ने सीखा अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील यह नहीं दिखा सके कि वह कौन सी सामग्री थी जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया था जिसे अपीलकर्ता ने बचाव के रूप में पेश किया था जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई।

9. यह न्यायालय एम.बी. सांघी, एडवोकेट बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य, एआईआर 1991 एससी 1834, एक ऐसे ही मामले की जांच करते समय देखा गया:

> "न्याय प्रणाली की नींव, जो इसे संचालित करने वालों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर आधारित है, हिल जाएगी यदि पीठासीन न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ दण्ड से मुक्ति के लिए अपमानजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की जाएंगी। अब समय आ गया है कि हम महसूस करें कि बहुप्रतीक्षित न्यायिक स्वतंत्रता खत्म हो गई है। न केवल कार्यपालिका या विधायिका से बल्कि उन लोगों से भी संरक्षित किया जाना चाहिए जो व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी स्वतंत्र समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

10. आशाराम एम. जैन बनाम ए.टी. में गुप्ता एवं अन्य। एआईआर 1983 एससी 1151, इस मुद्दे से निपटते समय, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "मुकदमेबाजी के तनाव और वैराग्य को वादियों को न्यायाधीशों की निंदा करके न्याय प्रशासन की प्रणाली को कलंकित करने, आतंकित करने और नष्ट करने की अनुमति

नहीं दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि न्यायाधीशों को संरक्षित करने की आवश्यकता है; न्यायाधीश अच्छी तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं। यह है उचित न्याय प्रशासन में जनता के अधिकार और हित की रक्षा की जानी चाहिए।"11. जेनिसन बनाम बेकर [1972] 1 ऑल ई.आर. 997, 1006 में, यह देखा गया, "[टी] कानून को चुपचाप बैठे नहीं देखा जाना चाहिए। जबकि जो लोग इसकी अवहेलना करते हैं वे स्वतंत्र हो जाते हैं, और जो लोग इसकी सुरक्षा चाहते हैं विश्वास खो देते है।"

12. अपीलकर्ता ने पूर्ण और बिना शर्त माफ़ी मांगी है जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है। माफ़ी का अर्थ विफलता के लिए खेदजनक स्वीकारोक्ति या बहाना है। किसी के कृत्य से प्रभावित व्यक्ति को यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि उसका कोई अपराध करने का इरादा नहीं था, साथ ही जो कुछ किया गया हो उसके लिए खेद की अभिव्यक्ति भी। माफी ईमानदारी से निर्विवाद होनी चाहिए। इसमें वास्तविक पश्चाताप और पश्चात्ताप की भावना समाहित होनी चाहिए, न कि सज़ा से बचने के लिए कोई सोची-समझी रणनीति

13. अधिनियम की धारा 12 का खंड 1 और उससे जुड़ा स्पष्टीकरण अदालत को अदालत की संतुष्टि के लिए माफी मांगने पर अदालत की

अवमानना करने के लिए दी गई सजा को माफ करने में सक्षम बनाता है। हालाँकि, किसी माफी को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि आरोपी ने माफी देर से मांगी हो एवं इस योग्य है कि आरोपी ने इसे सदभावी रूप से मांगी हो। ऐसा आचरण जो अदालत की न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है और उसका मजाक बनाता है, उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और कोई भी व्यक्ति इसे रोकने, पूर्वाग्रहित करने, बाधित करने या इसके साथ छेड़छाड़ कर न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां माफी मांगने की समझदारी बाद के चरण में ही सामने आती है। निस्संदेह, माफी किसी कार्य के लिए बचाव, औचित्य या उचित सजा नहीं हो सकती है जो अदालत की अवमानना के समान है। माफी उस स्थिति में स्वीकार की जा सकती है जहां जिस आचरण के लिए माफी दी गई है वह ऐसा है कि इसे "अदालत की गरिमा से समझौता किए बिना नजरअंदाज किया जा सकता है", या इसका उद्देश्य वास्तविक पश्चाताप का सबूत होना है। यह ईमानदार होना चाहिए. माफी उस स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती जब वह खोखली हो, उसमें कोई ग्लानि न हो, कोई पछतावा न हो या वह केवल कानून की कठोरता से बचने का एक उपाय हो। ऐसी माफी को केवल "कागजी माफी" कहा जा सकता है।

14. एलडी जैकवाल बनाम यूपी राज्य, एआईआर 1984 एससी 1374 में इस अदालत ने कहा कि वह अवमानना न्यायशास्त्र के प्रशासन में 'थप्पड़ मारो, माफी मांगो और भूल जाओ' विचारधारा की सदस्यता नहीं ले सकती। 'सॉरी' कहने से थप्पड़ मारने वाला विनीत नहीं हो जाता ।(यह भी देखें: टी.एन. गोदावर्मन थिनुमुलपाद बनाम अशोक खोत एवं अन्य, एआईआर 2006 एससी 2007)

इसलिए माफी "कागजी माफी" नहीं होनी चाहिए

दुख की अभिव्यक्ति दिल से होनी चाहिए, कलम से नहीं; क्योंकि 'सॉरी' कहना एक बात है, महसूस करना दूसरी बात है।

15. अदालत की आपराधिक अवमानना के लिए माफी जल्द से जल्द पेश की जानी चाहिए क्योंकि देर से मांगी गई माफी शायद ही "अपराध को दर्शाती है जो अवमानना के शुद्धिकरण का सार है। बेशक, माफी की पेशकश की जानी चाहिए और वह भी स्पष्ट रूप से और जल्द से जल्द अवसर पर हालाँकि, भले ही माफ़ी देर से न माँगी गई हो, लेकिन अदालत को लगता है कि यह वास्तविक पश्चाताप और पश्चाताप से रहित है, और यह पाती है कि यह केवल बचाव के हथियार के रूप में पेश की गई थी, तो अदालत इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकती है। यदि माफी की पेशकश उस समय की जाती है जब अवमाननाकर्ता को पता चल जाये कि

अदालत सज़ा देने जा रही है, तो एसी माफ़ी, माफी नहीं रह जाती है एवं एक कायरतापूर्ण कृत्य बन जाता है। (देखें: देबब्रत बंदोपाध्याय और अन्य एआइआर 1969 एससी 189;मुलख राज बनाम पंजाब राज्य, एआइआर 1972 एससी 1197;सचिव,हैलाकांडी बार एसोसिएशन बनाम असम राज्य एवं अन्य, एआइआर 1996 एससी 1925;सी. एलुमलाइ एवं अन्य। वी. एजीएल इरूदयराज एवं अन्य, एआइआर 2009 एससी 2214; और रणवीर यादव बनाम बिहार राज्य (2010) 11 एससीसी 493).

16. इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि दी गई माफ़ी को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और न्यायालय इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत माफ़ी को अस्वीकार करने और उसके लिए कारण दर्ज करते हुए सज़ा देने में सक्षम है। अपमानजनक भाषा का उपयोग किसी भी मामले में अवमाननाकर्ता को दोषमुक्त नहीं करता है। यदि सोचे समझे शब्दों का प्रयोग इस इरादे के साथ किया जावे कि उक्त शब्दों से किसी का अपमान हो, एवं मांगी गइ माफी में खेद, पश्चाताप, ग्लानि की कमी हो तो एसी माफी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। (देखें: श्री बरदाकांत मिश्रा बनाम उड़ीसा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और अन्य, एआईआर 1974 एससी 710; बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम.वी. दाभोलकर आदि, एआईआर 1976 एससी 242, आशाराम एम. जैन बनाम ए.टी. गुप्ता और अन्य। एआईआर 1983 एससी 1151; मोहम्मद जहीर खान बनाम विजय सिंह और अन्य,

एआईआर 1992 एससी 642; रे में संजीव दत्ता, (1995) 3 एससीसी 619, पटेल रजनीकांत धुलाभाई और अन्य बनाम पटेल चंद्रकांत धुलाभाई और अन्य, एआईआर 2008 एससी 3016; और विश्राम सिंह रघुबंशी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, एआईआर 2011 एससी 2275)।

17. अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायिक शक्ति की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसे अपने स्वभाव से ही बहुत सतर्कता और सावधानी से प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां "चुप्पी अब कोई विकल्प नहीं है।"(देखें: पुनः: एस. मुलगावकर एआईआर 1978 एससी 727; एचजी रंगनगौड बनाम मेसर्स स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य, एआईआर 2012 एससी 490: मनिंदरजीत सिंह बिटाव यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, (2012) 1 एससीसी 273; टीसी गुप्ता और अन्य बनाम हरि ओम प्रकाश और अन्य, (2013) 10 एससीसी 658; और अरुण कुमार यादव बनाम जिला न्यायाधीश के माध्यम से यूपी राज्य, (2013) 14 एससीसी 127)

अवमानना के लिए दंडित करने की अदालतों की शक्ति जनता को सुरक्षित करना है न्यायिक प्रक्रिया में सम्मान और विश्वास। इस प्रकार, यह न्याय की प्रत्येक अदालत के लिए एक आवश्यक घटना है।

18. बार का सदस्य होने के नाते, यह उनका कर्तव्य था कि वह

अदालत द्वारा दिए गए न्याय की महिमा का अपमान और निरादर न करें। यह एक ऐसा मरुस्थल है जहां एक प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के खिलाफ पूर्वाग्रह और पूर्वनिर्धारित दिमाग का आरोप लगाया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ इस तरह के गंजे, परोक्ष, निराधार आरोप लगाने से न केवल संबंधित न्यायाधीशों को पीड़ा और पीड़ा होती है, बल्कि न्याय प्रदान करने के कार्य में न्यायपालिका में जनता का विश्वास भी हिल जाता है। न्यायिक प्रक्रिया ईमानदारी, निष्पक्षता और निष्पक्षता पर आधारित है जो निर्विवाद है। विशेष रूप से बार के सदस्यों द्वारा ऐसा कृत्य, जो न्याय के पहिये का एक और हिस्सा हैं, अत्यधिक निंदनीय और गहरा खेदजनक है। प्रेरणा का अभाव कोई बहाना नहीं है.

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की माफी स्वीकार न करके कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि यह सदभावी नहीं है। हो सकता है कि आंतरिक आक्रोश रहा हो क्योंकि अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके भतीजे की हत्या कर दी गई है, लेकिन एक प्रैक्टिसिंग वकील के लिए अदालत के खिलाफ उंगली उठाने का यह कोई बहाना नहीं है।

20. अधिनियम की धारा 12(1) में प्रावधान है कि यदि अदालत संतुष्ट है कि अदालत की अवमानना की गई है, तो वह अवमाननाकर्ता को

साधारण कारावास से दंडित कर सकती है, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। रु. 2,000/- या दोनों के साथ।

धारा 12(2) में आगे प्रावधान है कि "तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी अदालत अपने या अपने संबंध में किसी भी अवमानना के लिए उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सजा से अधिक की सजा नहीं देगी।" इसके अधीनस्थ न्यायालय का।"

इस प्रकार, न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति अधिनियम की उपधारा (2) में निर्धारित सीमाओं के अधीन है।

21. इसलिए, उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता पर लगाया गया 20,000/- रुपये का जुर्माना घटाकर 2,000/- रुपये कर दिया गया है और उक्त जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया जाता है। तुरंत.

22. हमें अपील में कोई बल नहीं मिला, जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है। अपीलकर्ता को तुरंत सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ उसकी हिरासत सुरक्षित कर लेंगे और उसे सजा काटने के लिए जेल भेज देंगे। आदेश की एक प्रति सूचना एवं अनुपालन हेतु विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ को भेजी जाये।

निधि जैन

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नेहा खरे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।